आगाह करने के बावजूद सरकार को था इस हादसे का इंतजार

फ़रीदाबाद (म.मो.) शिक्षा के नाम पर अरबो रुपये खर्च करने का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार मासूम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। मजदूर मोर्चा ने गत अंक (1से 15 दिसंबर) में एनएच एक मार्केट में स्थित सरकारी हाई स्कूल की चरमराई व्यवस्था की खबर लिख कर सरकार और प्रशासन को चेताया था। लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद भी सरकार की नींद नहीं। जिसका खामियाजा स्कूल के पांचवीं कक्षा के छात्र यशपाल को भुगतना पड़ा।

गत 18 दिसंबर को घटना वाले दिन यशपाल अपने कुछ सहपाठियों के साथ स्कूल के समय से पहले पहुंच गया। ये बच्चे स्कूल शुरू न होने के कारण पिछले हिस्से में बने प्राथमिक पाठशाला के पुराने भवन में खेल रहे थे। रैम्प पर बना एक पिलर मरम्मत के अभाव में पहले से हिला हुआ था। खेलने के दौरान पिलर टूट कर यशपाल के पैर पर आ गिरा। जिससे यशपाल का पैर टूट गया। स्कूल के प्रिंसीपल ओमप्रकाश वहां पहुंच गए और उन्होंने बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया।

सरकारी की लापरवाही के कारण शहर के बीचों बीच स्थित स्कूल के बच्चों अपनी जान जोखिम में डाल कर पढ़ रहे हैं। हालांकि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए नया भवन मौजूद है। लेकिन स्कूल के ठीक बीच में मौजूद जर्जर भवन के कारण यहां बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। पुराने भवन को पीडब्ल्यूडी ने कई साल पहले कंडम घोषित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जर्जर भवन को सरकार ने आज तक तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की। जिसके कारण बच्चों की जान को हर समय खतरा बना रहता है। भोजन अवकाश के दौरान या फिर स्कूल का समय शुरू होने से पहले बच्चे अध्यापकों की नजर बचा कर पुराने भवन में खेलने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है। स्कूल के प्रिंसीपल द्वारा कई बार इस पुराने भवन को तोड़ने के लिए अर्जी लगाई जा चुकी है। प्रिंसीपल ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को पुराने भवन को तोड़ने के लिए कई बार अवगत करवाया है। डीईओ ने उन्हें बताया था कि भवन को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजा जाएगा। डीईओ के कहने पर उन्होंने करीब डेढ़ साल पहले अर्जी लिख कर डीईओ कार्यालय को भेज दी थी। जहां से फाइल पीडब्ल्यूडी के पास भेजी जा चुकी है। इसके बाद करीब छह महीने पहले वे रिमाइंडर भी भेज चुके है। इस भवन को तोड़ना तो दूर आज तक पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी इसका सर्वे तक करने नहीं पहुंचा।

इन हालातों को देख कर स्पष्ट है कि झूठे वायदों के दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा स्कूल के मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। स्कूल में बच्चों के घायल होने के बावूजद इलाके की विधायक सीमा त्रिखा अथवा सरकार का अन्य कोई मंत्री या नेता यहां झांकने तक नहीं आया।

नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से चरमराई शहरी व्यवस्था : कान में तेल डाल कर सोयी पड़ी सरकार

फ़रीदाबाद। (म.मो.) राम मंदिर और धर्म के नाम पर लोगों को बरगाला कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा सरकार को आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी कारगुजारियों से परेशान होकर नगर निगम के सफाई व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले पांच दिसंबर से हड़ताल पर थे। इससे शहर की सफाई समेत तमाम नागरिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लेकिन सरकार कर्मचारियों की समस्या का समाधान कर जनता की परेशानी दूर करने की बजाए चुप्पी साधे बैठी है। सफाई कर्मचारियों के बाद निगम का शेष स्टाफ भी 18 दिसंबर से टूल/कलम डाउन हड़ताल पर था जिससे नगर निगम में हर रोज अपने कामों के सिलसिले में आने वाले लोगों को इधर उधर धक्के खाने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। हर रोज निगम के कार्यालय में सैंकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न तरह के टैक्स जमा करवाने और जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने व अन्य कामों के सिलसिले में आते हैं। लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ रहा था।

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपये बर्बाद करने के बावजूद पहले ही शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई रहती है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हालत बद से बदतर हो गई है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। नालियां गंदगी से अटी पड़ी है। इस हालत के कारण शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। लगता है जैसे सरकार को लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है।

नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने बताया कि निगम में 688 कर्मचारी पिछले करीब पांच साल से ज्यादा समय से ठेकेदारी में पॉलिसी एक के तहत काम कर रहे है। यूनियन इन कर्मचारियों को पॉलिसी दो के तहत काम पर रखने की मांग कर रही है। निगम इन कर्मचारियों को सीधा वेतन देने की बजाए ठेकेदार के माध्यम से दे रही है, जिससे सरकार के खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। जिसका यूनियन विरोध कर रही है।

शास्त्री ने बताया कि सरकार ने शहर से कूड़ा उठाने का ठेका ईको ग्रीन कंपनी को दिया है। वे इस कंपनी में अपने समाज के लोगों को समायोजित करने की मांग कर रहे है। साथ ही वे इस कंपनी में काम पर रखने वाले कर्मचारियों को डीसी रेट पर वेतन देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी देने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शहर की आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों की संख्या है। ऐसे में वर्तमान में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे इन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती करने की मांग भी कर रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक पखवाड़ा बीत चुका है। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर समेत निगम के अधिकारियों से तीन बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन वे समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

दूसरी तरफ, युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्पलाइज फेडरेशन के प्रधान रमेश जागलान ने बताया कि हर महीने उनका वेतन पांच से सात तारीख के बीच आ जाता है। लेकिन इस बार करीब 15 से दिन ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वेतन उनके खाते में नहीं आया था। इसके अलावा सरकार ने सातवां वेतनमान तो लागू कर दिया। लेकिन उसका एरियर आज तक कर्मचारियों को देने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने बताया कि वे पिछले चार दिन तक टूल डाउन हड़ताल पर रहे। 21 दिसंबर को वेतन मिल जाने पर उन्होंने काम शुरू किया था।

कान में तेल डाल कर सोयी पड़ी सरकार की नींद आखिर टूट ही गयी। सरकार ने रूका वेतन देना मान लिया। यही काम पहले भी तो हो सकता था? कर्मचारियों व जनता को परेशान करना क्या जरूरी था? सरकार एवं उनके अधिकारियों की नालायकी का एक नमूना मात्र ही कहा जा सकता है चार दिन चली इस हड़ताल को। यह तमाशा केवल खट्टर सरकार का ही नहीं बल्कि इससे पूर्व की हुड्डा व चौटालों की सरकार में भी होता रहा है।

भगवान भरोसे चल रही है डबुआ कालोनी की डिस्पेंसरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर आम जनता के साथ मजाक कर रही है प्रदेश की भाजपा सरकार। सरकार ने दिखावे के लिए जगह जगह डिस्पेंसरियां तो खोल रखी है। लेकिन डिस्पेंसरियों में आने वाले मरीजों को इलाज के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा ही हाल है डबुआ कालोनी की सरकारी डिस्पेंसरी का।

घनी आवादी वाली डबुआ कालोनी की इस डिस्पेंसरी में एक मात्र डॉक्टर अजयपाल तैनात है। वह भी डेपूटेशन पर तैनात है। इसके अलावा अन्य कई तरह की जिम्मेदारी होने के कारण डा. अजयपाल भी डिस्पेंसरी में आने की बजाए अन्य सरकारी कामों में व्यस्त रहते हैं। डाक्टर के अलावा डिस्पेंसरी में तीन स्टाफ नर्स, एक क्लर्क, एक फार्मासिस्ट, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक काउंसलर और दस एएनएम तैनात है।

डिस्पेंसरी में प्रसूति कक्ष के अलावा टीबी के मरीजों के लिए डॉट सेन्टर भी मौजूद है।

23 दिसंबर को मज़दूर मोर्चा की टीम व्यवस्था देखने के लिए डिस्पेंसरी पहुंची तो पता चला कि यह किसी डाक्टर के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे चल रही है। सुबह नौ से दस बजे के लिए बीच डिस्पेंसरी में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं थे। जबकि वहां इलाज के लिए कई मरीज मौजूद थे। डॉक्टर के इंतजार में खड़े धौज गांव निवासी इकरामुद्दीन ने बताया कि वह यहां अपनी पत्नी मशरूम की टीबी की बीमारी का इलाज करवा रहा है और दवा लेने के लिए आया है। पिछले सात नवंबर को भी वह यहां दवा लेने आया था। उस समय यहां मौजूद एक कर्मचारी ने बताया था कि हड़ताल के कारण डाक्टर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारी ने उसे खुद ही दवा ले जाने के लिए कह दिया था। इकरामुद्दीन ने बताया कि यहां हर बार यहीं हालत देखने को मिलती है। करीब साढ़े दस बजे डिस्पेंसरी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां पहुंचा। पूछने पर उसने बताया कि डाक्टर पोस्टमॉर्टम ड्यूटी पर हैं। बीके अस्पताल में पूछने पर पता चला कि पोस्टमॉर्टम ड्यूटी पर डॉ. रोहित गौड तैनात है। डबुआ कालोनी निवासी बबीता ने बताया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट लेने के लिए सुबह नौ बजे से स्टॉफ नर्स का इंतजार कर रही है।

डाक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही के अलावा डिस्पेंसरी में चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल नजर आया। डाक्टर कक्ष के ठीक सामने बड़ी कुर्सी पर चार पिल्ले सोते नजर आए। सफाई के अभाव में चारों तरफ गंदगी तो फैली हुई थी। डिस्पेंसरी के पिछले हिस्से में किसी ने अवैध तरीके से झुग्गी बना कर कब्जा किया हुआ है। वहीं पर पंचर की दुकान का एक बोर्ड और कंडम हालत में दो बाइक भी खड़ी हुई थी। जिसे देख कर प्रतीत हो रहा था कि परिसर में पंचर की दुकान भी चलाई जाती है।

24 व 25 दिसंबर को सुबह छुट्टी के कारण डिस्पेंसरी बंद थी और प्रसूति कक्ष खुला हुआ था। लेकिन वहां न कोई स्टाफ नर्स न अन्य कोई मौजूद था। 26 दिसंबर को सुबह जब **मज़दूर मोर्चा** टीम डिस्पेंसरी पहुंची तो पता चला कि डबुआ कालोनी निवासी मरजीना नामक महिला की रात के समय प्रसूति हुई है। जच्चा-बच्चा और परिजन वार्ड में मौजूद थे। लेकिन स्टाफ नर्स और अन्य कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था।

इसी तरह 27 दिसंबर को सुबह दस बजे डिस्पेंसरी पूरी तरह खुली हुई थी और मरीजों की भीड़ भी लगी हुई थी। डाक्टर की गैर मौजूदगी में फार्मासिस्ट गीता अपनी मर्जी से ही मरीजों को दवा देकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। पूछने पर फार्मासिस्ट ने बताया कि डाक्टर साहब किसी काम से बीके अस्पताल गए हुए है। उसी दौरान डिस्पेंसरी में तैनात दो स्टाफ नर्स अपने बच्चों के साथ आकर अपनी हाजरी लगाती है और बाहर खड़े अपने परिजन की बाइक पर बैठ कर चली जाती है। इस स्थिति में डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों को किसी तरह का इलाज मिल रहा है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

डिस्पेंसरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र भडाना के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर ही मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद नागेंद्र भडाना ने इसकी हालत में सुधार करवाने के प्रयास करना तो दूर यहां कभी भी झांकने तक की जरूरत महसूस नहीं की। डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉ. अजयपाल ने बताया कि वे यहां डेपूटेशन पर तैनात है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें कई तरह के काम सौंप रखे हैं। उन्हें अक्सर कोर्ट में गवाही देने के साथ साथ पोस्टमॉर्टम ड्यूटी पर भी बुला लिया जाता है। जिसके कारण वे यहां अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी के पीछे बनी झुग्गी यहां पार्ट टाइम काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने जबरन कब्जा करके बनाई हुई। वे इसे हटवाने का प्रयास करते हैं तो स्थानीय नेताओं का दवाब उन पर पड़ने लगता है। इस सफाई कर्मचारी ने अपनी स्थाई नौकरी के लिए अदालत में केस भी दायर कर रखा है।

सेक्टर 12 का चौगिर्दा जाम: प्रशासनिक नालायकी का एक बेहतरीन नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीसियों बरस से सेक्टर 12 में ज़िला न्यायालय परिसर उपायुक्त कार्यालय सहित लगभग तमाम उपमंडल व तहसील कार्यालय मौजूद हैं। 'हूडा', जिसने यह सेक्टर बनाया उसका अपना कार्यालय भी यहीं स्थित है। सिफ़ारिशी, बेइमान व नालायक योजनाकारों की मुर्खता के चलते यहां बने लघु सचिवालय में अभी से जगह कम पड़ने लगी तो पुलिस कमिश्नर व ज़िला शिक्षा अधिकारी सहित अनेक कार्यालय इधर-उधर चल रहे हैं। भविष्य में जो कोई भी नये दफ़्तर आयेंगे या मौजूदा दफ़्तरों का विस्तार होगा, उनके लिये स्थान ही नहीं।

यह तो हालत रही दफ़्तरों की; इससे भी बुरी हालत बना छोड़ी है पार्किंग की। प्रशासन को पार्किंग ठेके के रूप में जो कभी 5 लाख वार्षिक मिलते थे अब बढकर 35 लाख के करीब हो गये हैं। मजे की बात तो यह है कि बीसियों बरस से इतनी मोटी वसूली करने के बावजूद प्रशासन द्वारा आज तक पार्किंग के लिये कोई नियत जगह नहीं बन पाई है। जगह के नाम पर 'हूडा' कार्यालय के बगल में नगर निगम के खाली पड़े प्लॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उस प्लॉट की क्षमता से दसियों गुणा वाहन सेक्टर के चारों ओर की सड़कों पर इस कदर होते हैं कि सड़कों से निकलना दूभर हो जाता है, हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है।

जनविरोधी सरकारों के मूर्ख योजनाकारों ने यह कभी सोचा ही नहीं कि एक के बाद एक भवन यहां बनाये जा रहे हैं तो आने वाले वाहन कहां खड़ें होंगे? पहली पांच मंजिला इमारत 1986 में बन कर तैयार हो गयी थी। इसमें पहले उपायुक्त कार्यालय और बाद में ज़िला न्यायालय आ गये थे। उस वक्त न तो इतने वाहन थे ओर न ही आसपास कोई अन्य इमारतें, चारों ओर बस खुले मैदान थे। इस लिये काम चलता रहा। कुछ बरसों बाद लघु सचिवालय की इमारत का निर्माण शुरू हुआ। उस वक्त यदि किसी ने पार्किंग की आने वाली समस्या का आंकलन कर लिया होता तो इमारत के नीचे पार्किंग हेतु एक या दो बेसमेंट तल बनाये जा सकते थे।

इसके बाद वकीलों का चेम्बर जब बनने लगे तो उस वक्त पार्किंग की समस्या भयानक रूप ले चुकी थी; उसके बावजूद भी किसी ने चेम्बरों के नीचे पार्किंग बेसमेंट बनाने की नहीं सोची। हाल ही में बनकर तैयार हुई न्यायीक परिषद् की नई इमारत के नीचे भी पार्किंग बेसमेंट की बात नहीं सोची गयी। इसी क्षेत्र में अभी 3-4 और भी सरकारी इमारतें बनने वाली हैं, लेकिन लगता नहीं कि कोई योजनाकार अथवा प्रशासनिक अधिकारी भूमिगत पार्किंग की बात सोच सकता है। इसी शहर में बने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 20 हज़ार वर्ग मीटर की एक व 12 हजार वर्ग मीटर की दूसरी भूमिगत पार्किंग बना छोड़ी हैं। जिनमें 5000 कारें पार्क की जा सकती हैं। यानी शासन-प्रशासन का एक हाथ दूसरे हाथ से भी सीखने को तैयार नहीं।